बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 176 ● नई दिल्ली ● शनिवार 12 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

यमुना को स्वछ बनाने पर मंथन, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक, रेखा गुप्ता रहीं मौजूद

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना नदी के पुनरुद्धार पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। चर्चा में यमुना नदी के पुनरुद्धार और पुनरुद्धार के लिए समन्वित प्रयासों और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे दिल्ली के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

दिल्ली में जलभराव पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, अब हर जगह चाहिए मिंटो रोड जैसा काम, दिए ये निर्देश

नई दिल्ली।

दिल्ली में बुधवार शाम तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुए जलभराव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की है. शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और जल विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं. राजधानी में जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं. दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री दफ्तर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि दिल्लीवासियों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही, रेखा गुप्ता ने ये कहा कि बारिश की वजह से समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए और जलभराव के मसले पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक में मौजूद अधिकारियों से मुख्यमंत्री कहा कि बारिश के दौरान तुरंत और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि जलभराव की स्थिति बनने से पहले ही उस पर काबू पाया जा सके.

नालों और नालियों की सफाई पर विशेष जोर

गुरुवार देर रात तक हुई बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव था. ऐसे में बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे बनी नालियों की नियमित जांच की जाए, जहां भी नाले या ड्रेनेज सिस्टम में कोई रुकावट हो, उन्हें तुरंत साफ कराया जाए. साथ ही,

छोटे नालों और नालियों की सफाई पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो पाए.

अधिकारी सड़कों पर पड़े कचरे पर विशेष ध्यान दें - रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के अधिकारी सड़कों पर पड़े कचरे पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सड़क किनारे, गलियों और नालों में पड़ा कूड़ा-कचरा जलभराव को जन्म देता है और अगर इसे समय पर हटाया जाए तो जलभराव की समस्या पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है. इसके अलावा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में जलभराव की पुरानी समस्या है, वहां जिस दिन बारिश हो, उस दिन आला अधिकारी दौरा करें और साफ-सफाई की निगरानी कर जल निकासी की व्यवस्था की जांच करें, ताकि जलभराव रोका जा सके.

सभी विभागों को 24×7 निगरानी रखनी होगी

दिल्ली सरकार के मुताबिक, बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली सरकार को लगातार फील्ड से जानकारी मिल रही थी कि जलभराव के चलते कई सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हुआ और लोगों को घर तक पहुंचने में लंबा समय लग गया. ऐसे में इसे देखते हुए अब सभी विभागों को 24×7 निगरानी रखनी होगी और विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है, ताकि जलभराव की समस्या को सामूहिक प्रयासों से समय रहते कंट्रोल किया जा सके.

इस बार की बारिश में दिल्ली के ऐतिहासिक मिंटो रोड और आईटीओ पर जलभराव नहीं हुआ था. ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि यही कार्यकुशलता अब पूरे शहर में दिखाई देनी चाहिए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इन दोनों जगहों पर जलभराव ना होने का श्रेय योजनाबद्ध प्रयासों को जाता है और जब इतने संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव को रोका जा सकता है, तो अन्य जगहों पर भी यही कार्यकुशलता दिखाई जा सकती है.

समयबद्ध लक्ष्य तय

ऐसे में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मॉनसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किया जाए, जिससे राजधानी में जलभराव की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.

कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; आरएसएस और पीएम पर बनाए थे विवादित कार्टून

नई दिल्ली। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित कार्टून साझा करने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उनकी याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हेमंत की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हेमंत मालवीय द्वारा दायर याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। मालवीय की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मामला एक कार्टून से संबंधित है, जिसे मालवीय ने 2021 में कोविड के दौरान बनाया था और उच्च न्यायालय ने कहा कि अर्नेश कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ऐतिहासिक मामलों, जो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित थे, का पालन नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कार्टूनिस्ट की निंदा की है। ग्रोवर ने कहा कि यह अपराध बीएनएस के अंतर्गत आता है, जिसके लिए अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने हाल ही में आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर विवादित कार्टून बनाए थे। अधिवक्ता और आरएसएस के स्वयंसेवक विनय जोशी ने हेमंत मालवीय के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने फेसबुक पर हेमंत मालवीय की प्रोफाइल देखी, जहां यह कार्टून पोस्ट किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सामग्री जानबूझकर आरएसएस और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से साझा की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री और भगवान शिव पर की गई टिप्पणियों को समाज में तनाव फैलाने वाला बताया। विवादित कार्टून में आरएसएस को उसकी पारंपरिक वर्दी (खाकी हाफ पैंट और सफेद शर्ट) में मानव रूप में दर्शाया गया था, जो झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। पीएम मोदी को स्टेथोस्कोप और इंजेक्शन के साथ दिखाया गया, जो वह आरएसएस के पीछे लगा रहे हैं। इसके साथ ही भगवान शिव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी जोड़कर पोस्ट को अधिक अपमानजनक बना दिया गया था। शिकायत के बाद हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की थी। मालवीय की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि उन्होंने यह कार्टून महज हास्य-व्यंग्य के उद्देश्य से अपने फेसबुक पेज पर साझा किया था। मंगलवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने मालवीय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने माना कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं लांघता है और आरोपी की पुलिस कस्टडी में पूछताछ जरूरी है हेमंत मालवीय के खिलाफ इससे पहले हरिद्वार के कनखल थाने में बाबा रामदेव ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर मालवीय द्वारा की गई एक पोस्ट को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा थाने में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मालवीय पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली में बड़ा हादसा, बाड़ा हिंदूराव इलाके में गिरी तीन मंजिला इमारत, एक शख्स की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में शुक्रवार तड़के तीन मंजिला इमारत गिरने से 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि मनोज शर्मा का शव मलबे में मिला. अधिकारी ने कहा कि इमारत गिरने की सूचना देर रात 1:56 बजे मिली थी. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत में कई दुकानें थीं.

फिलहाल मौके पर फायर और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है. बिल्डिंग के नीचे तीन दुकानें स्थित थीं, जिनमें सूटकेस, बैग और तिरपाल का कारोबार होता था. पहली मंजिल पर गोदाम बनाए गए थे. हादसे के वक्त बिल्डिंग के नीचे खड़ा एक ट्रक भी मलबे की चपेट में आ गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पास में मेट्रो का निर्माण कार्य भी चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि रात करीब 1:55 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फूल मिठाई के टोकरी वालान में बाड़ा हिंदू राव स्थित इमारत ढहने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दमकल विभाग, एनडीआरएफ, डीडीएमए और फॉरेंसिक क्राइम टीमों को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया था.मलबे और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया. रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में बाहर निकाला, जिसे तुरंत हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 46 वर्षीय मनोज शर्मा उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी था और पिछले 30 साल से दुकान पर काम कर रहा था. यह दुकान गुलशन महाजन नाम के एक व्यक्ति की थी. शुक्रवार सुबह तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा. सुबह की तस्वीरों में दो मशीनें मलबा हटाते हुए नजर आईं. इस घटना में अन्य किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

उम्मीद है कि तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आएगी...गौरव भाटिया का विपक्ष पर तंज

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है और यह राजद, कांग्रेस जैसे सभी अराजकतावादी दलों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिनका भारत के संविधान और भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। विपक्ष पर तंज कसते हुए भाटिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और वे आत्मनिरीक्षण करेंगे और फैसले का सम्मान करेंगे। प्रत्येक नागरिक और भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में लोकतंत्र फलता-फूलता रहे। वहीं, भाजपा प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को बरगलाने के लिए उठाए जाने वाले सवाल बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाने आ रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी में कहा है कि यह एक नियमित काम है और इस पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर को ''संवैधानिक दायित्व'' बताते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलें सुनीं और आयोग को सात करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले बिहार में एसआईआर जारी रखने की अनुमति दे दी।

नोएडा, फरीदाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, सड़कें पानी से लबालब

नई दिल्ली। राजधानी में मानसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर गुरुवार सुबह तक जारी रही। आज भी नोएडा, फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार शाम 5:30 बजे से बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे तक 37.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। इस साल मानसून ने 29 जून को दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों को कवर किया था। दिल्ली में मानसूनी बारिश की शुरुआत दो दिन देर से हुई। हालांकि इसके बाद से राजधानी में मानसून की बारिश बादातर धीमी और बिखरी हुई रही है। सामान्यतः जुलाई के महीने में दिल्ली में 209.7 मिलीमीटर बारिश होती है। पिछले साल जुलाई में 203.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 16 तारीख तक लगातार बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। शनिवार को भी कमोबेश मौसम को लेकर यही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी नीचे गिरकर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना है। गौतमबुद्ध नगर में गुरुवार सुबह करीब नौ बजे शुरू हुई बारिश ने लोगों को उमस से राहत दिलाई लेकिन जगह-जगह हुए जलभराव ने खूब सताया। प्रमुख मार्गों पर जलभराव के कारण वाहन रेंगते नजर आए। वहीं, नौकरीपेशा लोगों के साथ विभिन्न सेक्टरों व कालोनियों में रहने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। नौकरीपेशा करीब एक से डेढ़ घंटे की देरी से ऑफिस पहुंचे। जगह-जगह मेट्रो पिलर, फुटओवर ब्रिज और अन्य जगहों पर लोग बारिश से बचने के लिए खड़े रहे जिससे जाम लग गया। बारिश की वजह से दादरी-सूरजपुर-छलेरा रोड पर जगह-जगह पानी भर गया। इसके अलावा सर्फाबाद गांव की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कत हुई। चिल्ला बॉर्डर पर जलभराव और महामाया फ्लाईओवर के दोनों लूप पर पानी भरने से जाम लग गया। कई सेक्टरों की सड़कों में भी जलभराव होने से वाहन रेंगते रहे।

'कुंभकरणी नींद' में सोई सरकार, हालात बद से बदतर : कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सुपर सीएम प्रवेश वर्मा ने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में बाढ़ खत्म करने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है. यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा ने घोषणा की थी कि अब दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, जबकि हकीकत में शुरुआती बारिश ने ही राजधानी को पानी-पानी कर दिया है. यादव ने कहा कि मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही कांग्रेस ने सरकार को आगाह किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे नजर अंदाज कर दिया. सत्ता के नशे में डूबे मुख्यमंत्री और मंत्री आश्वासन देते रहे कि सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि दुपहिया वाहन पानी में डूब रहे है और दिल्ली की सड़कों तालाब में तब्दील हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस बदलाव की बात कर रही थी, वह दिल्लीवासियों के लिए और भी बुरा साबित हुआ है. कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया था, जिसे IIT की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाना था. रिपोर्ट को आए सात साल बीत चुके है, लेकिन न तो पिछली सरकार और न ही वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई की है. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभागों ने नालों की डी-सिल्टिंग का 80-90 फीसदी काम पूरा होने का दावा किया था, लेकिन सड़कों पर पसरा जलभराव इस दावे को झूठ साबित कर रहा है. देवेंद्र यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि डी-सिल्टिंग पर आई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें इसे दबा रही है.

आज से शुरू हुआ सावन का महीना, मंदिरों में भक्तों की जुट रही भीड़; केंद्रीय मंत्री ने भी किया जलाभिषेक

नई दिल्ली। आज से देशभर में सावन का महीना शुरू हो गया है। सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन मास की शुरुआत से पहले ही राजधानी दिल्ली के प्रमुख शिव मंदिरों में भव्य सजावट का कार्य संपन्न हो गया है। गुरुवार देर रात तक मंदिरों को फूलों की मालाओं, रंग-बिरंगी झालरों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया। चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर, झंडेवालान मंदिर, कालकाजी मंदिर, और उद्धाननाथ मंदिर सहित कई प्रमुख शिवालयों में सजावट का विशेष प्रबंध किया गया ।

अस्पतालों पर थोपे जा रहे अव्यवस्थित STP प्रबंधन के दबाव को समाप्त करने हेतु डॉक्टर प्रेम अग्रवाल की मांग

नई दिल्ली। (अजय कुमार चौधरी)नेशनल मेडिकल फोरम और दिल्ली हॉसपिटल फोरम के अध्यक्ष, संजीवन अस्पताल के चेयरमैन डॉ. प्रेम अग्रवाल ने राजधानी के अस्पतालों पर जबरन थोपे जा रहे अव्यवस्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) संचालन के दबाव के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल गैर-जरूरी है, बल्कि इससे अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को 2016 को गाइडलाइंस के अनुसार पहले से संचालित केन्द्रीय स्लुइक प्रणालियाँ पर्याप्त हैं, और इनमें ट्रीटमेंट के बाद अस्पतालों का जल रिसायकल हो रहा है।

इसके बावजूद अब दिल्ली के अस्पतालों को अपने-अपने स्तर पर स्लुइकस्थापित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह दोहराव वाली प्रक्रिया न केवल व्यर्थ है, बल्कि इससे डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ पर अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी बोझ भी पड़ रहा है। इससे आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। डॉ. प्रेम अग्रवाल ने माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप करने की अपील की है और तीन प्रमुख मांगें रखी हैं-

1. उन अस्पतालों को स्लुइकलगाने की बाध्यता समाप्त की जाए जो केन्द्रीय प्रणाली से जुड़े हैं।
2. दिल्ली की केन्द्रीय स्लुइक प्रणाली को और मजबूत किया जाए।
3. अस्पतालों को अनावश्यक वित्तीय और तकनीकी दबाव से मुक्त किया जाए।

भुवनेश्वर , कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष राहुल गाँधी,, के ,सी, वेणुगोपाल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में ओडिशा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

छाया-अशोका एक्सप्रेस ग्रुप

नोबेल शांति पुरस्कार अभी 2025 की घोषणा हुई नहीं परंतु 2026 के लिए दावेदारी का कार्ड शुरू

वैश्विक स्तरपर कुछ वर्षों में सारी दुनियाँ देख रही है की विशेष रूप से राजनीतिक वजन रखने वाले व्यक्ति अपने उस राजनीतिक वजन को बढ़ाने व मजबूत करने विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार पाने की जिज्ञासा रखते हैं, उसके लिए अंदरखाने उठापटक करते हैं,गुणाभाग करते है, ताकि वह पुरस्कार उनको मिल जाए, परंतु वे शायद यह भूल जाते हैं कि ऐसे भी कई लोग है जिन्होंने उस क्षेत्र में अपना पूरा जीवन, खुद स्वतम रहकर न्यौछावर कर दिया है, परंतु कभी पुरस्कार कि आस नहीं रखी। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए,जिसका टारगेट पुरस्कार नहीं वह संबंधित काम हो, वैचारिकता ऐसी होनी चाहिए कि मैं पुरस्कार के पास नहीं जाऊंगा, पुरस्कार मेरे पास चलकर आएगा,यह बात तब होती है,जब उसका काम बोलता है और पुरस्कार भी उसके पास दौड़े चले आता है।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से जोड़कर जो शांति नोबेल पुरस्कार की चर्चा चल रही है, व अभी पाक के बाद इजरायल ने भी ट्रंप का नॉमिनेशन कर दिया है परंतु दुनियाँ देख रही है, पाक- इजरायल का युद्ध में व्यवहार व दूसरी ओर अभी इजराइल- हमास रूस-यूक्रेन चरम पर है तो इधर भारत-पाक थाईलैंड- कंबोडिया तनातनी भी बनी हुई है, अभी तक इनके बीच शांति का कोई ठोस आधार नहीं है। चूंकि नोबेल शांति पुरस्कार अभी 2025 का घोषित हुआ ही नहीं है, परंतु 2026 के लिए दावेदारी का कार्ड शुरू हो गया है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,वैश्विक पुरस्कार (नोबेल या कोई भी) पानें का हकदार वही है, जो खुद नहीं उसका काम बोले, उसे मांगना नहीं पड़े उसे देने की मांग उठे,पुरस्कार चलकर उसके पास आए। साथियों बात अगर हम ट्रंप को संभाव्य नोबेल शांति पुरस्कार 2026 की जोरों पर हो रही चर्चा की करें तो,डायनामाइट के आविष्कारक और स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत कहती है कि नोबेल का शांति पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए,"जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ाने, स्थायी सेनाओं को समाप्त करने या कम करने, तथा शांति सम्मेलनों की स्थापना और संवर्धन के लिए सबसे अधिक या सर्वोत्तम कार्य किया हो, इजरायल और पाकिस्तान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस पुरस्कार के लिए भेजे जाने पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है कि इस पुरस्कार को किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं।गौरतलब है कि अब तक चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, इनके नाम हैं- थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलता तो वे इससम्मान को पाने वाले 5 वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे।नोबेल शांति पुरस्कारों को अक्सर राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है, नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट का स्वयं मानना है कि कुछशख्सियतें जिन्हें शांति पुरस्कार मिले है वे «अत्यधिक विवादास्पद राजनीतिक एक्टिविस्ट» रहे हैं। इन पुरस्कारों ने अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संघर्षों की ओर जनता का ध्यान भी बढ़ाया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को प्रेसिडेंट बनने के कुछ महीनों बाद ही यह पुरस्कार मिल गया था, इसपर काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी।1994 में एक सदस्य ने उस पद छोड़ दिया जब फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने इजरायल के शिमोन पेरेज और यित्जाक राबिन के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार साझा किया था। अब वर्ष 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने के बाद ट्रंप उत्साहित हैं, उन्होंने इस नॉमिनेशन के लिए इजरायल के पीएम की तारीफ भी की थी। ट्रंप लंबे समय से इस पुरस्कार के लिए खुद को दावेदार मानते हैं,फरवरी में बेंजामिन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा था,वे लोग सब कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे, ये बहुत गलत है, लेकिन मैं इसके योग्य हूं, पर वो मुझे देंगे नहीं, इसके बाद जून में इजरायल-ईरान के बीच लड़ाई हुई, इस जंग के बाद इजरायल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। बता दें कि ट्रंप को 2018, 2020 और 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी पैरवी शुरू कर दी है। 8 जुलाई को एक रैली में ट्रंप ने कहा हम एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिस पर कई दशकों में हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, यह शांति की कोशिश है और यह इजरायल के प्रयासों का नतीजा है, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो भी सकता है, आप जानते हैं कि यह एक अद्भुत बात है।«अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, «मैं यह अहंकार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, अब मुझे इसपर ओबामा का ख्याल आ रहा है, वो कितने अच्छे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जब ओबामा सत्ता में आए, तो उन्होंने कहा, %हम उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने जा रहे हैं इसपर ओबामा ने सचमुच कहा, «मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आठ साल तक कुछ नहीं किया, सचमुच «ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुछ ही हफ्तों में ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया। साथियों बात अगर हम नोबेल शांति पुरस्कार व ट्रंप की हड़बड़ी को जानने की करें तो, नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, इसकी स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत हुई थी, नोबेल पुरस्कार की छह श्रेणियां है, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है, अन्य पांच नोबेल पुरस्कार श्रेणियां हैं- भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान।नॉर्वे की नोबेल समिति इस पुरस्कार की विजेता तय करती है, हालांकि, नामांकन की अंतिम तारीख 31 जनवरी होती है, इसलिए, ट्रंप का नाम वर्ष 2026 के पुरस्कार के लिए माना जा सकता है,2025 के लिए नहीं।ट्रंप की हड़बड़ी के कुछ कारण (1)ओबामा से तुलनाट्रंप अक्सर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर इशारा करते है, जिन्हें अपनेकार्यकाल के शुरुआती महीनों में ही नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, ट्रंप खुद को एक महान शांतिदूत के रूप में स्थापित करना चाहते है, और ओबामा की उपलब्धि को पार करना चाहते है।(2)अपनी छवि को सुधारनाट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई विवादास्पद नीतियाँ अपनाई थीं, जिसके कारण उनकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई थी, नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें एक «शांतिदूत» के रूप में पेश करने का एक शानदार अवसर होगा, जो उनकी छवि को सुधारने में मदद कर सकता है।(3)2026 के राष्ट्रपति चुनाव में, ट्रंप को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, यह पुरस्कार उन्हें जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। (4) अंतर्राष्ट्रीय मान्यताट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने, इजरायल और अरब देशों के बीच शांति स्थापित करने और अन्य देशों में संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैनोबेल शांति पुरस्कार उन्हें इन दावों को साबित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। विवाद-हालांकि, ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रयास पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने वास्तव में शांति के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है, और उनका पुरस्कार के लिए प्रयास सिर्फ एक दिखावा है, कुछ का यह भी मानना है कि ट्रंप की विदेश नीति संघर्षों को सुलझाने के बजाय, उन्हें बढ़ावा देती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत,ट्रंप का गुणा भाग उतावलापन -शांति स्थापित करने के दावों का ठोस सबूत नहीं?-यह आसान नहीं?नोबेल शांति पुरस्कार अभी 2025 की घोषणा हुई नहीं परंतु 2026 के लिए दावेदारी का कार्ड शुरू, वैश्विक पुरस्कार (नोबेल या कोई भी) पानें का हकदार वही है, जो खुद नहीं उसका काम बोले, उसे मांगना नहीं पड़े उसे देने की मांग उठे,पुरस्कार चलकर उसके पास आए।

ढहते पुल -ध्वस्त सिस्टम

इतिहास का यह कालखंड पुलों के टूटने, दरकने और बहने के कालखंड के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल देश में मियाद पूरी होने के बावजूद भी बरकरार है लेकिन चार दशक पहले बनाए गए पुल भी दरकने लगे है। सभ्यताओं के निर्माण की वास्तविक कथा पुलों के बनने और बनाए जाने की कहानी है। पुलों से ही शहरों, गांवों और समाज का सम्पर्क और व्यापार बढ़ा है। सभ्यताओं ने इन्हीं पुलों के मजबूत ढांचों की बुनियाद पर खड़े होकर अपनी ऊंचाइयां हासिल की है। यह पुल अनायास नहीं गिर रहे लेकिन अफसोस कि एक के बाद एक पुल गिर रहे है। गुजरात के बड़ोदरा जिले में महिसागर नदी पर 4 दशक पुराना पुल अचानक ढहने से तेज रफ्तार दौड़ रहे कई वाहन नदी में गिर गए। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। बिहार में एक के बाद एक पुलों का गिरना आम बात हो गई है लेकिन गुजरात में हुए इस हादसे ने मोरबी पुल हादसे की याद ताजा कर दी, जिसमें लगभग 140 लोग मारे गए थे। इस हादसे से एक बार फिर सवाल खड़े हो गए है कि क्या यह हादसा मानवीय लापरवाही का परिणाम है? और इस हादसे के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते पुल गिर जाए तो हम इसे प्रकृति का प्रकोप मान लेते है लेकिन मुरम्मत किए जाने के बावजूद सामग्री की खराबी के कारण या रखरखाव की कमी या मानवीय चूक के चलते पुल ध्वस्त हो जाए तो इसे मौत का पुल ही कहा जाएगा। आसपास की आबादी का कहना है कि उन्होंने पुल को खतरनाक होने की जानकारी प्रशासन को दे दी थी और इस पुल पर आवाजाही बंद करने का आग्रह भी किया था ले किन सिस्टम सोया रहा जो लोगों की मौत का कारण बना। ब्रिज या पुल टूटने की यह कोई पहली घटना नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार, पिछले 10 सालों में भारत में 2,130 पुल ढह गए। इनमें से कई पुल निर्माण के दौरान ही गिर गए। पुलों के टूटने के कई कारण है, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, सामग्री की खराबी और ओवरलोडिंग शामिल है। अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई और कई लोग बह गए। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यसभा को जानकारी दी थी कि पिछले तीन सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 पुल ढह गए। इनमें से 15 पुल बने हुए थे और छह निर्माणाधीन थे। हर हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती। 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हुए है और सरकार के रोडमैप में बुनियादी ढांचे का विकास केन्द्रीय बिन्दु है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ललक पाले हुए है लेकिन बुनियादी ढांचे को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है। ईंट, गारे, लोहे, बजरी, सीमेंट के पुल जब भी गिरते है तो मरने वाले लोगों के परिजनों का क्रंदन, थोड़ा सियासी शोर, एक-दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी फोड़ने और सांठगांठ कर एक-दूसरे को साफ बचाने के कर्मकांड किए जाते है और बना दिए जाते है एक बार फिर गिरने के लिए नए पुल। गुजरात सरकार विकास के लगातार दावे करती आ रही है लेकिन पुलों का गिरना सबके लिए चिंता का विषय है। हैरानी की बात तो यह भी है कि हादसे के बाद प्रशासन से पहले ग्रामीणों ने वहां पहुंच कर देवदूतों की तरह काम किया और कई लोगों की जान बचाई। गुजरात का पुल हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। इस पुल को लेकर अब बहुत शोर मचाया जा रहा है कि राज्य में किसी भी ठेकेदार को ऑर्डर मिलने के बाद उससे कमीशन लिया जाता है और ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर निर्माण कर देते है, इसलिए हादसे के पीछे भ्रष्टाचार है। कई बार तो पुलों के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में 90 डिग्री पर दो पुल बनाए जाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे है। गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। पिछले पांच वर्षों में गुजरात में नए-पुराने या निर्माणाधीन पुल और फ्लाईओवर क्यों ढह रहे है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी हादसे के बाद सख्त कार्रवाई ही भविष्य में हादसों को रोक सकती है। पुल गिरने की घटनाएं सिर्फ मजाक नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर जब परिणाम ये हो कि पुल बनते ही गिर जाए, तो ये आम जनता के साथ मजाक के समान है। सवाल ये है कि क्या ऐसे पुलों से हमारा भविष्य सुरक्षित है? हर बार पुल गिरने के बाद ठेकेदार, इंजीनियर और प्रशासन एक-दूसरे पर दोष मढ़ने लगते है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पुल निर्माण के दौरान सही मानकों का पालन किया गया था? क्या गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग हुआ? या फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हर चीज को जल्दबाजी में निपटा दिया गया? समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहला और आवश्यक कदम यह है कि पुल निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और इंजीनियरों को सख्त जवाबदेही में लाया जाए। गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो और पुल निर्माण के दौरान पूरी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, जनता और सरकार को यह समझने की जरूरत है कि विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर होना चाहिए। ऐसे राज्यों में, जहां बाढ़ और नदियों की भरमार है, पुलों का सही तरीके से निर्माण होना बेहद जरूरी है। ये केवल पुल ही नहीं, बल्कि लोगों की जान और उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए है। पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक है। तो अगली बार जब कोई पुल बने, तो बस यही प्रार्थना करें कि वह पुल थोड़ी देर तक खड़ा रहे, क्योंकि अभी के हालात में तो पुल का गिरना ही आम बात हो गई है।

आशा-गौतम के हुनरगाथा में हुनर मंदों का जलवा

राजधानी के एक पंचसितारा होटल में सावन की घटा थीम पर पारंपरिक परिधानों को बड़े फलक पर प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया। आशा-गौतम के 'हुनरगाथा में हुनरमंदों का जलवा फैशन शो में पारंपरिक परिधान की धूम रही। आशा-गौतम के संयुक्त तत्वावधान के तहत स्वधा की मॉडल भी रैंप पर उतरीं। सावन के झूले, कजरी, मल्हार ये सभी संगीत भरी शाम को शानदार बना रहा था। जब संगीत को इस खूबसूरत परिधानों में सजी मॉडल रैंप पर उतरकर जीवंत कर दें तो इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा। मधुर लोकगीत की पृष्ठभूमि में जब सुंदर भारतीय पारंपरिक परिधानों में खूबसूरत मॉडल रैंप पर अदा के साथ चल रही थीं तो यह दृश्य अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कमल महल में सावन आ गया है और वर्षा की बूंदें गूंज रही है और साथ में मिट्टी की सोंधी-सोंधी महक भी वातावरण में छा गई थी। बड़ी उम्र की महिलाएं जब सुंदर भारतीय परिधानों में रैंप पर कैटवॉक करती हुई दिखीं तो मानो रैंप की शान बढ़ गई। इस शानदार फैशन शो की होस्ट आशा-गौतम की जोड़ी ने कहा कि सपना कोई एक देखता है लेकिन उसे साकार करने में बहुत लोगों का हाथ होता है। इस अवसर पर स्पेशल शो की डायरेक्टर रश्मि वीरमानी, स्पेशल ओलंपिक की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा, पंजाब केसरी की सीएमडी एवं वरिष्ठ केसरी क्लब की अध्यक्ष किरण चोपड़ा, गीताबेन मनसुखभाई मांडविया, सुरभी तिवारी, बबीता मल्होत्रा, उदयपुर की महारानी महिमा कुमारी सिंह, नीलम प्रताप रूडी, सुधा धींगरा, सोनल कालरा, पूनम शर्मा, जयंती तान्या, तमन्ना खेना एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहीं। स्वधा की चेयरपर्सन वर्षा गोयल ने कहा कि सपना हमने देखा, स्वधा ने देखा और इस सपने को हम सबने मिलकर साकार किया। यह शो केवल 45 मिनट का नहीं था, इसके पीछे बहुत से लोगों की दिन-रात की मेहनत थी। आशा गौतम के साथ मिलकर स्वधा के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं नीलम प्रताप रूडी ने कहा कि एक मंच पर पारंपरिक भारतीय परिधानों की खूबसूरती को देखकर वह अचंभित है। हस्तशिल्प और कारीगरी को प्राप्त ऐतिहासिक गौरव दोबारा मिलेगा। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इस कार्यक्रम में रामपुर के कारीगरों की ओर से तैयार किए गए पारंपरिक पोशाकों की पेशकश फैशन शो के माध्यम से की गई। जरदोजी, चटपटी जैसी ऐतिहासिक हस्तकला का प्रदर्शन किया गया। ऐतिहासिक हस्तशिल्प से तैयार परिधानों को देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फैशन शो हर उस महिला को एक नई दिशा देना चाहता है जिसके पास कोई न कोई हुनर है और जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। बता दें कि 25 वर्षों से भी अधिक की विरासत के साथ, आशा गौतम ने पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल को निरंतर नए सिरे से परिभाषित किया है, विरासत को नवीनता के साथ मिलाकर कालातीत उत्कृष्ट कृतियां रची है।

सम्पादकीय...

मोटापे का श्राप

वजन कम करना अब सिर्फ बाहरी रूप या सौंदर्य से जुड़ी कोई सनक नहीं रह गयी है, न ही यह अब केवल 'साइज जीरो' जैसी दिखने की चाह तक सीमित है। यह उससे कहीं अधिक गंभीर और व्यापक विषय बन चुका है। यह अब अच्छे स्वास्थ्य और शरीर से अनावश्यक व हानिकारक चर्बी को कम करने की दिशा में एक जरूरी प्रयास है। यह मधुमेह और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को रोकने या देर से उत्पन्न होने से बचाने के बारे में है। तो अब सवाल यह उठता है कि व्यक्ति क्या करे? क्या उस वजन तुला को एक ओर रख दे जो बार-बार मनचाही संख्या दिखाने से इनकार करता है? या फिर लगातार उस पर चढ़ता रहे और हर बार निराश होकर उतरता रहे? यह बात सच है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। वे वजन घटाने के लिए जी-जान से कोशिश करते हैं, पर अधिकांश प्रयास असफल हो जाते हैं। भारत में महिलाओं में मोटापे की दर 1990 में 1.2 फीसदी थी, जो 2022 में बढ़कर 9.8 फीसदी हो गई। पुरुषों में यह दर 0.5 फीसदी से बढ़कर 5.4 फीसदी हो गई। लैंसेट की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे की स्थिति चिंताजनक है, शहरी आबादी का लगभग 70फीसदी हिस्सा अधिक वजन वाला है। विश्व स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 24% से अधिक महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में मोटापा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक पाया जाता है, विशेषकर महिलाओं में। मोटापा कई गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोगों का एक प्रमुख जोखिम कारक है। अब सवाल उठता है, मोटापा है क्या और इसे मापा कैसे जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स जो शरीर में वसा का अनुमानित माप होता है, 30 या उससे अधिक हो, तो उसे मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स की गणना व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि मौंजारो न केवल रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बल्कि भूख को भी कम करता है, जिससे वजन में कमी आती है। एक अन्य महत्वपूर्ण औषधि है सेमैग्लूटाइड, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न नामों से जानी जाती है और हाल ही में भारत में उपलब्ध कराई गई है। इन औषधियों को लेकर चिकित्सा क्षेत्र में विशेष चर्चा हो रही है और देश के प्रमुख अंतःस्रावी विशेषज्ञ, जैसे डॉ. अम्बरीश मित्तल इन्हें मधुमेह एवं वजन नियंत्रण के लिए उपयोगी बता रहे हैं। डॉ. मित्तल ने इन औषधियों के माध्यम से वजन प्रबंधन पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इनके लाभों के साथ-साथ संभावित हानियों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। वे स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि इन औषधियों का सेवन केवल चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए न कि केवल सुविधा या आकर्षण के चलते। ये औषधियां दोनों ही प्रकार के प्रभाव रखती है, कुछ लाभकारी, तो कुछ संभावित हानिकारक भी। ये नई पीढ़ी की औषधियां भूख को अत्यधिक रूप से कम करती हैं और रोगियों को बिना बार-बार भूख लगे, आहार में आवश्यक परिवर्तन अपनाने में सहायता करती हैं लेकिन इनसे जुड़े दुष्प्रभाव भी है। सबसे प्रमुख रूप से मांसपेशियों की क्षति तथा औषधि बंद करने के बाद वजन का पुनः बढ़ना। यदि डॉ. मित्तल से पूछा जाए, तो वे कहते हैं कि जब भी वजन घटता है, कुछ मात्रा में मांसपेशियां भी कम होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 15 किलोग्राम वजन कम करता है, तो उसमें लगभग 4 किलोग्राम मांसपेशियों का नुकसान संभव है, जो कि अत्यधिक है। उनके शब्दों में 'समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप वजन घटाते हैं और फिर वह वापस आ जाता है। जो वापस आता है वह केवल चर्बी होती है, मांसपेशियां फिर से नहीं बनतीं। यदि कोई व्यक्ति इस चक्र से तीन बार गुजरता है, तो मांसपेशियों का अत्यधिक नुकसान होता है और चर्बी फिर से जमा हो जाती है। अतः शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम और पर्याप्त प्रोटीन का सेवन अनिवार्य है। हालांकि इन औषधियों को लेकर कुछ आशाएं भी जुड़ी हुई हैं। मांसपेशियों को सुरक्षित रखने वाली दवाओं पर शोध चल रहा है और यदि यह सफल होता है, तो यह पूरे उपचार पद्धति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण साबित हो सकता है। फिर भी, इस कमी के बावजूद इन औषधियों के लाभ उनके संभावित जोखिमों की तुलना में कहीं अधिक हैं। रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि आने वाले समय में ऐसी अनेक औषधियां उपलब्ध होंगी जो अधिक जटिल या शरीर पर प्रभाव डालने वाली नहीं होंगी और उपयोग में आसान भी होंगी। फिर भी चिंताजनक पहलू यह है कि इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। मितली आना, पाचन संबंधी समस्याएं, कब्ज, पित्ताशय में पथरी और दस्त। चेतावनी यही है कि इनका सेवन केवल योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। साथ ही, जिन व्यक्तियों को थायरॉयड कैंसर या अग्न्याशयशोथ (पैंक्रियाटाइटिस' का पूर्व इतिहास रहा हो, उनके लिए ये औषधियां उपयुक्त नहीं हैं। एक और गंभीर बात यह है कि ये औषधियां सभी पर समान रूप से प्रभाव नहीं दिखातीं, कुछ लोगों को वजन घटाने में अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। इनका उपयोग अकेले करना या वे लोग जो वास्तव में इन औषधियों के जरूरतमंद नहीं है, यदि इन्हें केवल दिखावे के लिए ले रहे हैं और फिर मनमाने ढंग से बंद कर रहे हैं तो यह अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। एक अन्य नकारात्मक पक्ष यह है कि जैसे ही इन औषधियों का सेवन बंद किया जाता है, वजन दोबारा बढ़ने की आशंका रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये औषधियां केवल तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक इनका नियमित सेवन किया जाए। सेवन बंद होते ही वजन पुनः बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त ये कोई तीन माह का सीमित उपचार नहीं है। विशेषज्ञों का मत है कि जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन आरंभ करता है, उसे कम से कम एक से दो वर्षों तक नियमित रूप से इनका सेवन करना होता है, और कुछ मामलों में यह जीवन भर की दवा भी बन सकती है। इसलिए भले ही इन औषधियों को लेकर काफी उत्साह और चर्चा हो रही हो, यह समझना आवश्यक है कि ये कोई 'जादुई दवाएं' नहीं है जिन्हें मात्र 'साइज जीरो' की चाह में अपनाया जाए। इनका सेवन केवल तभी किया जाना चाहिए जब चिकित्सक द्वारा आवश्यकता के अनुसार सलाह दी जाए। केवल इसलिए नहीं कि व्यक्ति वजन घटाना या बेहतर दिखना चाहता है। ऐसे लक्ष्यों के लिए आहार, व्यायाम और जीवनशैली में सुधार जैसे उपाय कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली हैं।

सस्ता गोल्डन वीजा भारत को पड़ेगा महंगा

साल 2019 से 2022 के बीच यूएई ने 1.5 लाख से ज्यादा गोल्डन वीजा जारी किए थे और 2025 में 5,000 भारतीयों के आवेदन की उम्मीद है। 23.3 लाख रुपये की फीस से ही अगर 5,000 भारतीय आवेदन करें तो उसे करीब 1167 करोड़ रुपये की इनकम होगी। इसके अलावा यूएई को रियल एस्टेट और उपभोक्ता बाजार में भी फायदा होगा, क्योंकि वीजाधारक वहां घर किराए पर लेंगे, खरीदेंगे, और अपने बच्चों की पढ़ाई व इलाज पर खर्च करेंगे। वियतनाम पिछले कुछ सालों में लगातार पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश बनता जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल टैलेंट और इनवेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए वियतनाम ने अब एक नई कोशिश की है। वियतनाम ने एक नया 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। इस वीजा का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों सहित वैश्विक निवेशकों, व्यापारियों और पेशेवरों को आकर्षित करना है, यह प्रोग्राम देश में निवेश, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वियतनाम सरकार ने इस वीजा योजना को लॉन्च किया, जिसमें भारतीयों को विशेष रूप से टारगेट किया गया है वियतनाम ने भारतीयों को इस प्रोग्राम का प्रमुख लक्ष्य बनाया है, क्योंकि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।

मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने अपने वीजा संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा पाना आसान हो गया है। यूएई सरकार ने नामांकन आधारित एक नए प्रकार का गोल्डन वीजा शुरू किया है। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता है टैलेंट और पैसे का जाना। जब पढ़े-लिखे, समझदार प्रोफेशनल यूएई जैसे देशों में बसने लगेंगे तो भारत की रीढ़ मजबूत करने वाले लोग देश से दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सस्ता गोल्डन वीजा भारत को पड़ सकता है महंगा! टैलेंट और पैसा दोनों चला जाएगा केरल और पंजाब पहले से ही बड़े पैमाने पर पलायन झेल रहे हैं। अब जब गोल्डन वीजा इतना सस्ता हो गया है, तो इन राज्यों से और ज्यादा लोग बाहर जाने लगेंगे। इससे स्थानीय लेबर की कमी हो सकती है, जिससे खेती, छोटे कारोबार और घरेलू सेवाओं पर असर पड़ेगा। ऐसे में भारत से न सिर्फ पैसा, बल्कि टैलेंट और मेहनतकश लोग भी धीरे-धीरे बाहर निकल सकते हैं। दरअसल, यूएई एक स्मार्ट चाल चल रहा है। यूएई खुद को न्यूयॉर्क या लंदन जैसे ग्लोबल सिटी की तरह बनाना चाहता है, जहां दुनियाभर से टैलेंट और निवेश आए। वह दुनियाभर के होनहार लोगों को अपने देश में बुला रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में। जाहिर है कि भारतीय प्रोफेशनल्स और उद्यमी वहां नए बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे यूएई को टैक्स और रोजगार दोनों मिलेगा। उसका मकसद है कि वह तेल पर निर्भरता कम करके एक नॉलेज-बेस्ड इकोनॉमी बने। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीजा शुरू किया है, जो नामांकन पर आधारित होगा, हालांकि इसमें कुछ शर्तें होंगी, जो कि यहां संपत्ति या व्यवसाय में बड़ी मात्रा में निवेश करने की वर्तमान प्रथा से अलग है। अब तक भारत से दुबई का गोल्डन वीजा पाने का एक तरीका संपत्ति में निवेश करना था, जिसका मूल्य कम से कम एईडी दो मिलियन (4.66 करोड़) होना चाहिए, या देश में व्यापार में बड़ी राशि का निवेश करना था। लाभार्थियों और प्रक्रिया में शामिल लोगों ने बताया कि नई नामांकन-आधारित वीजा नीति के तहत, भारतीय अब एईडी 1,00,000 (लगभग रु.23.30 लाख) का शुल्क देकर आजीवन यूएई के गोल्डन वीजा का आनंद ले सकते हैं। तीन महीने में 5,000 से अधिक भारतीय इस नामांकन-आधारित वीजा के लिए आवेदन करेंगे। यूएई में निवास चाहने वालों की बड़ी तादाद रही है। ऐसे में ये फैसला भारतीयों के लिए एक राहत लेकर आया है। गोल्डन वीजा हासिल करने वाले को इससे कई लाभ मिलेंगे। वे अपने परिवार के सदस्यों को यूएई ला सकते हैं। वे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं और यूएई में व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। छात्रों को भी गोल्डन वीजा मिल सकता था, लेकिन उसके लिए हाई स्कूल में 95 फीसदी से ज्यादा नंबर या यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा जीपीए होना जरूरी था। इसके अलावा, मानवीय काम करने वाले लोगों को भी यह वीजा मिल सकता था, अगर उनके पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो या वे एईडी 2 मिलियन का योगदान दे चुके हों।

इस वीजा के परीक्षण के प्रथम चरण के लिए भारत और बंगलादेश को चुना गया है, तथा भारत में नामांकन-आधारित गोल्डन वीजा के प्रारंभिक स्वरूप का परीक्षण करने के लिए रयाद ग्रुप नामक कंसल्टेंसी को चुना गया है। यूएई सरकार की पहल और इस वीजा के लिए पहले देश के रूप में भारत का चयन भारत और यूएई के बीच मजबूत व्यापारिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है, जो मई 2022 से प्रभावी दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के बाद और मजबूत हो गए हैं। गोल्डन वीजा नामांकन प्रक्रिया यूएई और इसके (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते) सीईपीए हस्ताक्षरकर्ता/भागीदार देशों के बीच एक समझौता है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो भारत और बंगलादेश? के साथ शुरू हुआ है और जल्द ही इसमें चीन और अन्य सीईपीए देश भी शामिल हो जाएंगे। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता है टैलेंट और पैसे का बाहर जाना। जब पढ़े-लिखे, समझदार प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट्स यूएई जैसे देशों में बसने लगेंगे, तो भारत की रीढ़ मजबूत करने वाले लोग देश से दूर हो जाएंगे। साल 2023 में ही करीब 16 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता ली थी, जिनमें बड़ी संख्या खाड़ी देशों की थी। अब जब गोल्डन वीजा इतना सस्ता हो गया है, तो यह संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही, इस प्रक्रिया में जो फीस और रहन-सहन का खर्च होगा, वह भी करोड़ों रुपये भारत से बाहर ले जाएगा। साल 2019 से 2022 के बीच यूएई ने 1.5 लाख से ज्यादा गोल्डन वीजा जारी किए थे और 2025 में 5,000 भारतीयों के आवेदन की उम्मीद है। 23.3 लाख रुपये की फीस से ही अगर 5,000 भारतीय आवेदन करें तो उसे करीब 1167 करोड़ रुपये की इनकम होगी। इसके अलावा यूएई को रियल एस्टेट और उपभोक्ता बाजार में भी फायदा होगा, क्योंकि वीजाधारक वहां घर किराए पर लेंगे, खरीदेंगे, और अपने बच्चों की पढ़ाई व इलाज पर खर्च करेंगे। वियतनाम पिछले कुछ सालों में लगातार पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश बनता जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल टैलेंट और इनवेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए वियतनाम ने अब एक नई कोशिश की है। वियतनाम ने एक नया 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। इस वीजा का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों सहित वैश्विक निवेशकों, व्यापारियों और पेशेवरों को आकर्षित करना है, यह प्रोग्राम देश में निवेश, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वियतनाम सरकार ने इस वीजा योजना को लॉन्च किया, जिसमें भारतीयों को विशेष रूप से टारगेट किया गया है वियतनाम ने भारतीयों को इस प्रोग्राम का प्रमुख लक्ष्य बनाया है, क्योंकि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारतीय उद्यमी, विशेष रूप से तकनीकी और स्टार्टअप क्षेत्र में, वियतनाम की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए उत्साहित हैं। अब गोल्डन वीजा पाना बच्चों का खेल सा बन चुका है, ये दिखने में तो एक शानदार लाइफ चेंजिंग ऑफर लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है भारत के लिए खतरे की घंटी। ऐसे में भारत की सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिससे लोग भारत छोड़ने की बजाय यहीं रहकर काम करना पसंद करें। जैसे कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, नौकरियों के मौके बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधारना होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैनेलभेला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08863)

राज्य में कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की हाई लेवल मीटिंग

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून- व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री वीरवार को देर सायं राज्य में कानून- व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों पर पुलिस कार्रवाई, पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पुलिस तंत्र और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने और जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने फिरौती के मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे गंभीर अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ कार्य करें ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और उनमें यह विश्वास बना रहे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों और कन्या विद्यालयों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बच्चों से संवाद कर उन्हें सजग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्राओं और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बना रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं से संवाद करके विभिन्न हॉटस्पॉट और संवेदनशील रूट चिह्नित किए है। इन स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात है और पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुरक्षा उपायों की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार नए कदम उठाए ताकि महिलाओं और छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या भय का सामना न करना पड़े।

प्रदेश में अपराध की स्थिति की करी समीक्षा, दिए सख्त निर्देश
अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए - मुख्यमंत्री
फिरौती मामलों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से करें काम, अपराधियों पर करें सख्त कार्रवाई
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को रखे चाक-चौबंद
नशे व मादक पदार्थों के मामलों में कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों की तय करें जिम्मेवारी - नायब सिंह सैनी

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को रखें चाक-चौबंद

नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों या प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर भीड़-भाड़ के समय, प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, अन्य संवेदनशील स्थानों पर हालातों का नियमित जायजा लेकर अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गाशक्ति फोर्स भी विशेष पेट्रोलिंग करें।

नशे व मादक पदार्थों के मामलों में कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों की तय करें जिम्मेवारी

राज्य में नशा एवं मादक पदार्थों के मामलों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों और उसके सेवन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सरकार युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस और समन्वित अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'नशा मुक्त हरियाणा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही, थानों में दर्ज नशा संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते हुए पाए गए, तो तुरंत होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली और जनता के अनुकूल बनाने हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में फील्ड स्टाफ को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय या वर्दी में शराब का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, ऐसे में अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें, शिकायतकर्ता को मिले न्याय

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए देते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा उन्हें लिखित रूप में सौंपी गई शिकायतें, जो जन संवाद पोर्टल पर दर्ज की जाती है, उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी त्वरित संज्ञान लें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेना शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ताओं को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए और उसके निवारण की प्रगति नियमित रूप से जन संवाद पोर्टल पर अपडेट की जाए।

जन संवाद को बढ़ावा दें, एक्सटॉर्शन मामलों में हो त्वरित कार्रवाई

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी आमजन से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, तो प्रशासन और पुलिस की छवि मजबूत होगी और जनता का विश्वास भी पुलिस के प्रति बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक्सटॉर्शन सेल बनाकर विशेष टीमों के रूप में काम करते हुए जबरन वसूली जैसे मामलों की गहन जांच की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और समाज में एक सख्त संदेश जाए।

थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को शिकायत की रिसिप्ट/प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान करें

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में पुलिस गश्त और चौकसी को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसके साथ ही, थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को उनकी शिकायत की रिसिप्ट/प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पीड़ित को उचित समय पर न्याय मिल सके। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करें तथा आमजन से सीधा संवाद स्थापित करें। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो सकेगा, बल्कि जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ होगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान की जाए। चिह्नित अपराधों, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, महाधिवक्ता हरियाणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

30 व 31 जुलाई को आयोजित होगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जाएगा। इनमें 30 जुलाई को लेवल-3 (पीजीटी) एवं 31 जुलाई को लेवल-2 (टीजीटी) व लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेशभर के 673 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) तथा शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षा की तिथि एक होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 26 व 27 जुलाई, 2025 के स्थान पर अब 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा 30 जुलाई (बुधवार) को सायंकालीन सत्र में 3:00 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 399 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 1,20,943 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। उन्होंने बताया कि लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा 31 जुलाई (वीरवार) को प्रात कालीन सत्र में 10:00 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होगी, इस परीक्षा में 673 परीक्षा केन्द्रों में कुल 2,01,517 अभ्यर्थियों प्रविष्ट होंगे। इसी तरह लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा भी इसी दिन यानि 31 जुलाई (वीरवार) को सायंकालीन सत्र में 3:00 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 280 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 82,917 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा आरम्भ होने से 2 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा ताकि केन्द्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमैट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य प्रक्रियाएं समय रहते पूरी हो सकें। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षाओं की पल-पल की मानिटरिंग करने के उद्देश्य से भिवानी बोर्ड मुख्यालय पर एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है।

इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी. सुरेश ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की समीक्षा बैठक

पानीपत।

समाधान शिविर में आई समस्याओं का अधिकारी रुचि लेकर करें समाधान: निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी

हरियाणा सरकार में इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों और अधिकारियों से वर्चुअल समीक्षा बैठक कर समाधान शिविर में आई शिकायतों के अति शीघ्रता से समाधान करने की निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो समाधान शिविर में जो शिकायतें नागरिकों द्वारा दर्ज कराई जाती हैं उनका अति शीघ्रता से समाधान करें। समीक्षा बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द शेष बची समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि शिकायतों के निदान को लेकर अधिकारियों ने अच्छे परिणाम दिए है। अधिकारियों को इसे बरकरार रखना है। अतिरिक्त आयुक्त ने समीक्षा बैठक के बाद विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों के साथ जनता समाधान शिविर में दर्ज शिकायतों को दूर करने को लेकर बातचीत की व कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उनके विभाग अनुसार समस्याएं भी बताई व जल्द से जल्द उनका समाधान करने के लिए कहा। निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने कहा कि अधिकारी मुख्य तौर पर दो बातो पर विशेष ध्यान दें। एक तो जो पेंडेंसी बचती है उनका शीघ्रता से निदान करें व दूसरा रिओपन होने वाली शिकायतों के निदान पर और जोर लगाएं व उन्हें क्लियर करें। उन्हें अच्छी तरह से अटैंड करें।

इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों की जो भी पेंडेंसी बचती है उनको एक - एक करके बताया। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर किरण, नगराधीश टीनू पोसवाल, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अमित पेरिवा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश शर्मा, पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता सावित पानु, डीएनओ शार्दुल शंकर, बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता एम एस धीमान, डीएफएससी कुमारी नीतु, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ आत्मा राम गोदारा, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल, जिला खेल अधिकारी धुरेंद्र कुमार, उप निदेशक पशु पालन विभाग डॉ संजय आंतिल, संजीव शर्मा, फायर अधिकारी गुरमेल सिंह आदि मौजूद रहे।

प्रदेश में हर वर्ग की समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार कर रही विकास कार्य : कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार

पानीपत।

मनरेगा के तहत खेतों के रास्तों को किया जा रहा पक्का
कैबिनेट मंत्री ने उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया और अन्य विभागो के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

हरियाणा के पंचायत और खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति जानी व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरओ कनबा लाकड़ा ने सचिवालय पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का बुके देकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में विकास को प्राथमिकता देकर तेजी से विकास कार्य कर रही है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में समानता पूर्वक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिकारी जहां-जहां विकास कार्य हो रहे हैं उन स्थानों का समय निकाल कर निरीक्षण भी करें और कार्य में और तेजी लाने का प्रयास करें। उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को आश्वस्त किया कि सभी विकास कार्य निश्चित समय अवधि में पूर्ण किए जाएंगे। जिन - जिन विभागों के अंतर्गत ये विकास कार्य आते हैं उन विभागों के अधिकारियों को इन विकास कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल ने बताया खंड मडलौडा में मनरेगा के तहत खेतों के रास्ते पक्के करने का कार्य किया जा रहा है। कुल 24 रास्तों में ज्यादातर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसराना खंड के खेत के कुल 20 रास्तों को बनाने का तेजी से किया जा रहा है। इसमें कुछ का कार्य बचता है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों से खेत खलियान योजना की प्रगति की जानकारी भी ली। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर दहिया, सीईओ डॉक्टर किरण के अलावा कार्यक्रम अधिकारी रणसिंह वर्मा के अलावा कई अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।

हमारा लक्ष्य सिर्फ आँखों की रोशनी नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को उज्जवल बनाना : आरती सिंह राव

चण्डीगढ़।

स्वास्थ्य मंत्री ने हिसार जिले से किया उज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से उज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया। यह राज्यव्यापी अभियान विशेष रूप से स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने और 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह अभियान नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष बजट प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत 1.4 लाख से अधिक चश्मों का एक साथ वितरण किया जाएगा, जो कि राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 50 उपमंडलीय अस्पतालों और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा और अनूठा अभियान है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत 14 हजार 267 राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 21 लाख छात्रों की आंखों की जांच की जाएगी, जिनमें से 40 हजार जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। साथ ही, 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की मोतियाबिंद की जांच भी की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकारी या एनजीओ अस्पतालों में निःशुल्क सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। राज्य स्तरीय उज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान के तहत विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नेत्र जांच और चश्मा वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वस्थ समाज की ओर अग्रसर करने की एक ठोस पहल है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आंखों की रोशनी बहाल करना नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाना है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दृष्टि दोष, मोतियाबिंद के बाद अंधत्व का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और समय रहते उपचार न हो तो यह स्थायी अंधत्व में बदल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जो कॉर्नियल अंधापन के इलाज के लिए प्राइवेट और एनजीओ अस्पतालों में निःशुल्क ट्रांसप्लांट हेतु 15 हजार रुपये की सहायता देता है। हर साल राज्य में 800 से अधिक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉर्ड है। इस उद्देश्य के लिए 22 आई डोनेशन सेंटर्स भी संचालित है। कैबिनेट मंत्री ने जनता से नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा, आपका एक नेत्रदान किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार आधुनिक उपकरण, मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं के जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

एक नजर

सरचार्ज माफी योजना 2025 का लाभ उठाएं बिजली उपभोक्ता: डीसी

पानीपत। जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई 'सरचार्ज माफी योजना 2025' के तहत अब उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान केवल मूल राशि के आधार पर कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत 31 अगस्त 2024 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 11 नवंबर 2025 तक लिया जा सकता है। उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने बिजली उपभोक्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र उपभोक्ता समय रहते इस योजना से जुड़ें, बकाया बिलों का निपटान करें और भविष्य में नियमित भुगतान की ओर बढ़ें। इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जिला बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग, नगर निकाय और पंचायत भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। योजना के तहत यदि उपभोक्ता बकाया बिल की पूरी राशि एकमुश्त जमा करते है, तो उन्हें मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल संबंधी मामले न्यायालय में लंबित है, यदि वे केस को स्वेच्छा से वापस लेते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक कराएं आवेदन

खरीफ फसलों का बीमा करवाएं किसान, कम प्रीमियम में पाएं व्यापक सुरक्षा
खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम फसल बीमा योजना

पानीपत। डीसी डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक योजना में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, कपास, मक्का और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया। डीसी ने बताया कि यह योजना किसानों को बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को धान, बाजरा, मक्का और मूंग की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास की फसल के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। योजना की विशेषता यह है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से यदि खेत स्तर पर फसल को नुकसान होता है, तो किसान को उस नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दिया जाएगा। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जलभराव के कारण होने वाली क्षति भी योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे हर साल करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे है। बीमा के लिए आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। डीसी ने किसानों से आह्वान किया गया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने खेत व फसलों को संभावित आपदाओं से सुरक्षित करें। उपायुक्त ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए आश्वस्त बनाती है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते योजना से जुड़ें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग कार्यों की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में युवाओं की लेगी सेवाएं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया निर्णय

चंडीगढ़। हरियाणा में अब प्रोफेशनल्स युवा विभिन्न विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता और तय समयावधि में उनके पूरा होने तक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योग्य युवाओं की «चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स» के रूप में सेवाएं ली जाएंगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गुणवत्ता में कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा और उत्साह के साथ सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (ग्रेड्स) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है और इनके चयन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2023 में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की, जिसे इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इनमें गुणवत्ता प्रोटोकॉल को व्यवस्थित करना और लागू करना, तकनीकी गुणवत्ता ऑडिट, मानक संचालन विधियां और प्रक्रियाएं विकसित करना, गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, थर्ड-पार्टी निगरानी एजेंसियों और डिज़ाइन एवं डीपीआर सलाहकारों का पैनल तैयार करना, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधाओं को मजबूत करना, नवीनतम तकनीकों और डिजिटल टूल्स को अपनाना, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण विधियों को प्रोत्साहित करना, और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के चल रहे प्रमुख विकास कार्यों का गुणवत्ता ऑडिट करने के निर्देश दिए, ताकि उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ तय समय में परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारियों के सुचारू निष्पादन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों या परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के मामलों में, जवाबदेही केवल ठेकेदार तक ही सीमित नहीं होगी। परियोजना की देखरेख करने वाले संबंधित सरकारी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और यह जवाबदेही उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में विधिवत रूप से दर्शाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में शामिल कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि सभी इंजीनियरिंग विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) या अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। ये कार्यशालाएं उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों से अवगत रहने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई विस्तृत मानक संचालन विधियों और प्रक्रियाओं, विशेष रूप से अंक प्रणाली (मार्किंग सिस्टम) की सराहना की। उन्होंने प्राधिकरण को तुरंत तकनीकी ऑडिट करने और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को अंक प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ठेकेदारों को किए जाने वाले सभी भुगतानों को अंक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, किसी भी कमी या घटिया बुनियादी ढांचे की स्थिति में न केवल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, बल्कि संबंधित सरकारी अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि वह परियोजना के निरीक्षण से लेकर परियोजना के पूरा होने तक सरकार द्वारा प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स का चयन करके तकनीकी ऑडिट शुरू करें। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्राधिकरण ने राज्यभर में विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कई गतिविधियां संचालित की हैं। सड़कों, भवनों, जल आपूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, विद्युत प्रसारण और वितरण जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों के लिए तकनीकी गुणवत्ता मानदंड विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही, डीपीआर एवं डिजाइन कंसलटेंट, थर्ड-पार्टी निरीक्षण एजेंसियां और गुणवत्ता पर्यवेक्षक भी पैनल में शामिल किए गए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने हरियाणा को दिया ऑफर, इस जगह का रखरखाव करेगी दिल्ली सरकार, कहा- बजट की कमी नहीं

नई दिल्ली। पिछली आप सरकार में दिल्ली और हरियाणा के बीच खींचतान का मुद्दा बनी मुनक नहर पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में ऑफर दिया कि हरियाणा सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार दिल्ली के भीतर आने वाले 20 किलोमीटर मुनक नहर के हिस्से का रखरखाव करने के लिए तैयार है और दिल्ली सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है. आज दिल्ली सचिवालय में मुनक नहर के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के भी अधिकारी शामिल थे. बैठक में कहा गया कि असल में हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करके 20 किलोमीटर तक बहने वाली मुनक नहर से दिल्ली को लगभग 200 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी मिलता है, जो कि राजधानी की कुल पाइप लाइन जल आपूर्ति का लगभग 21फीसदी है और दिल्ली के करीब 20 लाख लोगों के घरों में इसी नहर का पानी साफ होकर पाइप लाइन से पहुंचता है, लेकिन दिल्ली में बवाना से इंद्रलोक तक बहने वाली इस मुनक नहर के दिल्ली के हिस्से के भी रखरखाव व उसके आसपास की जमीन हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के पास है.दिल्ली सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक में हरियाणा सरकार के अधिकारियों से कहा कि उन्हें जानकारी है कि इस नहर का रखरखाव बेहतर नहीं है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में हरियाणा के अधिकारियों से शिकायती लहजे में कहा कि दिल्ली में मुनक नहर खुले में बहती है और नहर व पानी की सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था भी हरियाणा की तरफ से नहीं की गई है. साथ ही दिल्ली सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बहने वाला मुनक नहर का हिस्सा कई स्थानों पर कच्चा भी है, जिसके चलते इसका पानी प्रदूषित होता रहता है. साथ ही नहर के अंदर का पाट भी हरियाणा द्वारा रखरखाव के अभाव में कई जगहों पर टूट गया है जिसकी वजह से नदी दूषित भी हो रही है और बाधित भी. शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक आज बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों से कहा कि - अगर आपको इस नहर के रखरखाव में कोई समस्या आ रही है तो हमें इस नहर के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, हमारी पास बजट की कोई कमी नहीं है और दिल्ली के संबंधित विभाग इसका संचालन व रखरखाव बेहतर कर पाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के अधिकारियों को बताया कि वह मुनक नहर को दिल्ली सरकार के अधीन में लाने के लिए जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भी बात करेंगी. इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है ऐसे में अगर मुनक नहर दिल्ली सरकार के अधीन आ जाए तो इस पूरी योजना को जल्द व प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार मुनक नहर का रखरखाव खुद इसलिए करना चाहती है ताकि नहर को और मजबूती प्रदान की जाए और उसके जल प्रवाह में कोई समस्या न आए, साथ ही दिल्ली सरकार नहर की गहराई को भी समान करना चाहती है .

ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए डोभाल कहा-

एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए; हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए

चेन्नई ।राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारत को नुकसान की खबरें चलाईं। उन्होंने कहा कि विदेश मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। ना यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। डोभाल ने यह बात शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही। वे कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया, वो किया लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट्स की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। इस दौरान सेना ने 100 आतंकी मार गिराए थे। दोनों देशों के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सीजफायर पर सहमति बनी थी। डोभाल ने कहा, टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। हमें गर्व है कि इस दौरान हमने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की। हमने सीमापार नौ पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला किया था। इनमें एक भी ठिकाना बॉर्डर के पास नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक थे। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने कहा, आप एक ऐसे देश, एक ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, जो हजार सालों से संकटग्रस्त और लहूलुहान रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र की इस धारणा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितना अपमान और तकलीफ सही होगी। राष्ट्र, राज्य से अलग होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों सालों से अस्तित्व में है।

बिहार के मतदाताओं को वंचित होने से बचाएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश; कांग्रेस का भाजपा पर निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश (जिसमें बिहार में चल रही चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई) स्पष्ट करता है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने रोक लगाने की मांग नहीं की थी। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि यह फैसला बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर होने से बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को वैध मानकर विचार किया जाए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इसे संवैधानिक दायित्व बताया और चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की दलीलों को सुनने के बाद बिहार के सात करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए चल रही प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को अब बिहार की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार करना होगा। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को वंचित होने से बचाया जा सकेगा।रमेश ने अपनी पोस्ट के साथ कोर्ट के आदेश के स्क्रीनशॉट भी साझा किए। उन्होंने आगे कहा, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार की रोक लगाने की मांग नहीं की गई थी। आदेश के पेज नंबर सात में यह साफ लिखा है। चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे पर गुमराह करने वाली हेडलाइन बनाना एक संवैधानिक संस्था को शोभा नहीं देता। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जयराम रमेश पर सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना बंद कीजिए। कोर्ट ने किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज को स्वीकार करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि कहा है कि आयोग चाहे तो उन पर विचार कर सकता है। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग के पास किसी दस्तावेज को खारिज करने का अधिकार है, बशर्ते वह कारण स्पष्ट करे। मालवीय ने रमेश को चेतावनी दी कि कोर्ट की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश करना खतरनाक है और अवमानना का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, ऐसा ही काम राहुल गांधी ने किया था और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी।

राधिका मर्डर केस में खुलेंगे कई राज : आरोपी पिता को एक दिन की पुलिस रिमांड

इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता ने की हत्या

घर में ही 3 गोलियां मारीं; बेटी के एकेडमी चलाने से नाराज था

गुरुग्राम । गुरुग्राम के सेक्टर-57 के सुशांतलोक-2 में गुरुवार की सुबह करीब 11.30 बजे महिला टेनिस खिलाड़ी को उसके पिता ने तीन गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेनिस खिलाड़ी के अकेडमी चलाने पर नाराजगी के चलते पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसी पीठ में गोली मार दी। राधिका यादव को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव (करीब 25 वर्ष) के रूप में हुई, जोकि अपने परिवार के साथ सेक्टर-57 स्थित सुशांतलोक-2 में रहती थी। मृतका राधिका एक टेनिस अकेडमी चलाती थी और उसके पिता (आरोपी) टेनिस अकेडमी चलाने की बात से खुश नहीं थे। मृतका के साथ टेनिस अकेडमी चलाने को बात पर हुए विवाद के चलते बृहस्पतिवार को राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से तीन गोली उसकी पीठ में मार दी। गोली लगने के बाद राधिका का चाचा कुलदीप और चचेरा भाई उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। टेनिस खिलाड़ी को गोली मारने की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (पूर्व), सेक्टर-56 थाने के प्रभारी, एफएसएल, सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमें घटनास्थल पहुंची। जिस घर में गोली मारी गई थी, पुलिस ने वहां पर साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी रखवाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि राधिका ने टेनिस खेल में कई पदक भी जीते हैं। कुछ माह पहले कंधे में चोट लगने के कारण राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया था।

इसके बाद राधिका ने वजीराबाद गांव में बच्चों को टेनिस सिखाने के लिए अकादमी शुरू की थी, लेकिन राधिका के पिता दीपक इस अकादमी को खोलने के खिलाफ थे। अकादमी खोलने के बाद राधिका के पिता नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि गांव में जब वह कभी निकलते हैं तो गांव वाले उसे बेटी की कमाई खाने संबंधी बात कहते हैं। इस बात को लेकर पिता दीपक काफी परेशान रहता था। बीते 15 दिनों से पिता व बेटी में टेनिस अकादमी को लेकर झगड़ा चल रहा था।

ओडिशा में राहुल गांधी की संविधान बचाओ रैली, बोले- जल, जंगल, जमीन चुराना चाहती है भाजपा

ओडिशा । कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को ओडिशा में संविधान बचाओ रैली नामक एक जनसभा में भाग लिया। यह सभा पार्टी द्वारा समर्थन जुटाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। इस दौरान राहुल ने भाजपा पर जमकर वार किया।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार का बस एक ही काम है - राज्य की गरीब जनता के हाथों से ओडिशा की संपत्ति छीनना। पहले बीजद सरकार यही करती थी और अब भाजपा सरकार यही कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और मजदूर है, तो दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और भाजपा सरकार है। यह लड़ाई जारी है। ओडिशा की जनता के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ता ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं, कोई और नहीं। राहुल ने आगे कहा कि मैं कल बिहार में था। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की गई, वैसी ही कोशिश बिहार में भी हो रही है। चुनाव चोरी के लिए चुनाव आयोग ने एक नई साजिश रची है। चुनाव आयोग भाजपा की शाखा की तरह काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच एक करोड़ नए मतदाता जुड़े। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि ये मतदाता कौन थे और कहां से आए। हमने चुनाव आयोग से कई बार मतदाता सूची और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन चुनाव आयोग ने हमें ये नहीं दिए। वे बिहार में भी वही चोरी करने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में की गई थी। मैं कल बिहार गया था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन के नेताओं के साथ मैंने कहा कि हम चुनाव आयोग और भाजपा को बिहार चुनाव की चोरी नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अडानी ओडिशा सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी चलाते हैं। जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जब जगन्नाथ यात्रा के रथ खींचे जाते हैं, तो लाखों लोग इसे देखते हैं और इसके पीछे चलते हैं। फिर, एक नाटक होता है - अडानी और उनके परिवार के लिए रथ रोक दिए जाते हैं। इससे आपको ओडिशा सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह ओडिशा सरकार नहीं है, यह अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इसका लक्ष्य आपकी जमीन, जंगल और भविष्य को लूटना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी आपसे जल, जंगल, जमीन चुराना चाहती है। उन्होंने आगे कहा क कुछ नया शुरू हो गया है। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। आज तक पता नहीं चला कि ये महिलाएं कहां गईं। यहां हर रोज महिलाओं पर अत्याचार होता है। उनके साथ बलात्कार होता है। ओडिशा में हर रोज 15 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। आपकी सरकार चौबीसों घंटे सिर्फ आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता- जिनके डीएनए में कांग्रेस है। आप हमारे बब्बर शेर हैं, जो ओडिशा की जनता को रक्षा करते हैं। ओडिशा की बीजेपी सरकार का सिर्फ एक काम है, ओडिशा का धन गरीब जनता से चोरी करना। पहले बीजेपी की सरकार यह करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर हैं। वहीं, दूसरी तरफ पांच-छह अरबपति और बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ओडिशा की जनता के साथ मिलकर, इस लड़ाई को जीत सकता है, और कोई नहीं।

चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, 125 किलो डायनामाइट के साथ तीन गिरफ्तार

देहरादून ।

सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना त्यूणी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑल्टो कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

चेकिंग के दौरान वाहन से 125 किलोग्राम डायनामाइट, दो डब्बे डेटोनेटर, लाल तार का रोल और एक बंडल बत्ती बरामद हुई। कार सवार आरोपी विस्फोटक ले जाने के वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तीनों आरोपी रिंकू, रोहित और सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाना त्यूणी में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है।

बीजेपी को मिल सकता है नया चेहरा, इस दिग्गज नेता के नाम पर मुहर लगभग तय, सिर्फ ऐलान बाकी!

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद पर बनाए रखने का फैसला किया गया था। अब जब चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है, संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक, अधिकांश राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं, जो कि पार्टी अध्यक्ष के चयन की पूर्वशर्त होते हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व की नजर नए अध्यक्ष के चयन पर है, जिसकी घोषणा जुलाई के अंत तक हो सकती है। पार्टी संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नामांकन करते हैं, और यदि कोई विरोध नहीं होता तो आम सहमति से अध्यक्ष की घोषणा होती है।

कंगना को राजनीति में नहीं आ रहा मजा, बोली - सैलरी भी है कम, लाखों में होता है खर्चा

मुंबई । बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने के बाद अब राजनीति में कदम रखा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीत हासिल की थी और सांसद बनीं। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि कंगना राजनीति की दुनिया में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहीं। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी सांसद की सैलरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहती हूं कि राजनीति एक बहुत महंगा शौक है। जब उनसे शौक जैसे शब्द के इस्तेमाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर आप ईमानदार हैं, तो सांसद की भूमिका को प्रोफेशन के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि इस काम से आपको नौकरी जैसी आमदनी नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि, हमें जो वेतन मिलता है, उसमें से कुक और ड्राइवर की तनख्वाह देने के बाद हमारे पास केवल 50-60 हजार रुपये ही बचते हैं। जानकारी के अनुसार, एक सांसद को भारत सरकार की ओर से करीब 1.24 लाख रुपये का मासिक वेतन मिलता है। कंगना ने बताया कि अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में कहीं भी यात्रा करने पर लाखों रुपये का खर्च आता है। हर जगह कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर होती है, ऐसे में जब आप स्टाफ के साथ कार से यात्रा करते हैं तो खर्च लाखों में पहुंच जाता है। यह सच में बहुत महंगा शौक है। बहुत से सांसदों का बिजनेस होता है, वे वकील के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझसे पहले संसद में आए, जैसे जावेद अख्तर जी, वे भी अपने प्रोफेशन से जुड़े रहे। आपको राजनीति के साथ काम करना होता है। कुछ दिन पहले भी कंगना ने कहा था कि उन्हें राजनीति में मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि लोग मेरे पास टूटी नालियों और सड़कों की शिकायतें लेकर आते हैं, जबकि सोशल वर्क मेरा बैकग्राउंड नहीं है।

चुनाव से पहले सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, पेंशनधारियों के खातों में ट्रांसफर किए 1227 करोड़ रुपए

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास से 1.11 करोड़ लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित की और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक को 1,100 रुपये प्रदान किए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से कुल 1,227.27 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए गए।

इस कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उपस्थित थे। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 400 रुपये प्रदान करते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विधवाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल सके। नीतीश ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हमलोग निरंतर प्रयासरत हैं ताकि सभी एक सम्मानजनक तथा बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। विपक्ष और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसमें उनका कोई खास योगदान नहीं है। 2005 से पहले कोई न कोई कुछ करता था, हम (राजद के साथ) गलती से दो बार वहाँ गए थे, लेकिन क्या इन लोगों ने कुछ खास किया है? उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजनीति का एक नया युग शुरू होगा और इस बात पर जोर दिया कि सभी मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर देखते हुए कहा, हम भविष्य में कभी इधर-उधर नहीं जाएंगे, बल्कि राज्य के विकास के लिए साथ-साथ चलेंगे।

एक देश एक चुनाव से नहीं होगा संविधान का उल्लंघन, संसदीय समिति को पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने दिया सुझाव

नई दिल्ली ।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) ने एक देश एक चुनाव मसौदे को लेकर संसदीय समिति को सुझाव दिए हैं। पूर्व सीजेआई ने समिति को बताया है कि एक देश एक चुनाव से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। दोनों न्यायाधीशों ने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई । भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक देश एक चुनाव विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति से बात की। सूत्रों ने बताया कि संसदीय समिति की आठवीं बैठक में दोनों न्यायविदों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। उन्होंने देश में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों यू. यू. ललित और रंजन गोगोई ने क्रमशः फरवरी और मार्च में समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने विचार रखे थे। दोनों ने एक साथ चुनाव कराने की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उन्होंने विधेयक के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिए थे। एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के अधिकांश लोग और नेता एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार का समर्थन करते हैं। पांच राज्यों और

एक केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने के बाद चौधरी ने कहा कि कई राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, हालांकि कुछ लोगों को इस पर चिंताएं भी हैं। उन्होंने कहा कि समिति इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। हम पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अध्ययन दौरे पर गए थे। महाराष्ट्र में, हमने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राजनीतिक दलों के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात की। हम जहां भी गए, हमने देखा कि सभी दलों के समिति सदस्य इस मुद्दे में सच्ची दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम सभी दलीय सीमाओं से परे, देश के हित में क्या बेहतर है, इस बारे में सोच रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए दो विधेयक बीते साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किए गए थे। ये विधेयक हैं- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक।

इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए जरूरी बदलाव करना है। 12 दिसंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इन विधेयकों को मंजूरी दी थी। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के विरोध को देखते हुए इन्हें संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।

39 सदस्यीय इस संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला, मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी, सुषमा स्वराज और संबित पात्रा आदि सांसद इस समिति के सदस्य हैं। संयुक्त संसदीय समिति में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।